(e) if not, what is the institutions-wise/ bank-wise position of remaining portion] of such loans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Reserve Bank of India (RBI) has reported that financial institutions extend term loans to private and public sector companies as well as subscribe to the equity of such companies in the primary market. Banks also provide loans to private and public sector companies and invest in equity of such companies subject to RBI guidelines. The investment institutions like the Life Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India, however, subscribe to the shares of such companies in the primary as well as secondary maiket. The investment decision of the banks/institutions is based on their commercial considerations.

(d) to (e) In accordance with the practices and usages customary amongst banks and in conformity with provisions of statutes governing public sector banks and financial institutions as also the provisions of Public Financial Institutions (Obligations as to Fidelity and Secrecy) Act, 1983, the information relating to individual constitutents cannot be divulged.

ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

159. **श्री अजीत जोगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशि और कार्यशील पूंजी कितनी-कितनी हैं;

(ख)गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों से कितने ग्राहक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग)उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई और कितनी राशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0 वी0 चन्द्रशेख मूर्ति) : (क) संभवत: माननीय संसद सदस्य का आशय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं जिनकी 1607 शाखाओं का नेट-वर्क हैं।। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशि और कार्यशील निधि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख)और (ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण खार्तों की संख्या और इनके द्वारा दी गई ऋण राशि तथा वसूल की गई ऋण राशि नीचे दी गई हैं:-

(लाख रूपए)

वरण	1991-92	1992-93	1993-94
दिए गए ऋण			
(i) खातों की संख्या	99056	70909	69260
(ii) राशि	4660	3589	4495
वसूली	4415	4623	5281

Bogus Policies of LIC

160. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have seen Press Report published in Indian Express of 23rd June, .1995 under the caption "Bogus policies cost LIC Rs. 500 crores annually";

(b) if so, the number of bogus policies together with the amount during the last three years, year-wise and the names of the zones/districts with large number of bogus policies;

(c) the number of policies sold/lapsed during the period and the total loss incurred by LIC; and